

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2004/आषाढ़ 30, 1926

No. 644]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2004/ASADHA 30, 1926

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

का.आ. 835(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किए गए निम्नलिखित आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—
आदेश

डॉ. सुब्रमणियन स्वामी ने वर्तमान लोक सभा के आसीन सदस्य, श्री राहुल गांधी को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के खण्ड (ब) और (ड) के अधीन लोक सभा सदस्य होने से निरहता करने के लिए तारीख 5-6-2004 को एक अर्जी प्रस्तुत की थी;

और, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन इस प्रश्न पर चुनाव आयोग से यह राय चाही थी कि क्या श्री राहुल गांधी निरहता के अध्वधीन हो गए हैं;

और, चुनाव आयोग ने इस पर अपनी यह राय (उपाबंध द्वारा) दी है कि सुस्थिर संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री राहुल गांधी की अधिकथित निरहता का प्रश्न, यदि है भी तो, पूर्व-निर्वाचन की निरहता का मामला है और इसे संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता या उनके द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इसलिए वर्तमान अर्जी राष्ट्रपति के समक्ष पोषणीय नहीं है।

अतः, अब मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह विनिश्चित करता हूँ कि डॉ. सुब्रमणियन स्वामी की अर्जी पोषणीय नहीं है और इसलिए अस्वीकार की जाती है।

16 जुलाई, 2004

भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

कोरम :

माननीय श्री बी. बी. टंडन

निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री टी. एस. कृष्णामूर्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री एन. गोपालास्वामी

निर्वाचन आयुक्त

2004 का निर्देश मायला संख्या 1

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) सपठित संविधान के अनुच्छेद 102(1) (ब) और (ड) के अधीन लोक सभा के आसीन सदस्य श्री राहुल गांधी की अधिकथित निरहता।

श्री सुब्रमणियन स्वामी

बनाम

श्री राहुल गांधी के मामले में

राय

तारीख 15 जून, 2004 का, भारत के राष्ट्रपति का यह निर्देश नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (घ) और (ङ) के अधीन श्री राहुल गांधी, लोक सभा के आसीन सदस्य की अधिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय लेने की ईप्सा से किया गया है।

2. उपर्युक्त प्रश्न डॉ. सुब्रमणियन स्वामी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 5 जून, 2004 की अर्जी से उद्भूत हुआ है। उनकी अर्जी में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए, अभी हाल ही में हुए साधारण निर्वाचन में अमेठी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री राहुल गांधी की अधिकथित निरर्हता के संबंध में अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति के विनिश्चय की ईप्सा की गई है।

3. यह सुस्थिर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन संसद् के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता का प्रश्न विनिश्चित करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता सिर्फ सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता के संबंध में उद्भूत होती है। संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाने पर अधिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न में जांच करने की इसकी (निर्वाचन आयोग की) अधिकारिता भी सिर्फ निर्वाचन पश्चात् निरर्हता की दशा में उत्पन्न होती है। पूर्व-निर्वाचन निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न के अर्थात् ऐसी निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व अध्यक्षीन था, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग VI के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन अर्जी द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य रीति से नहीं। इस संबंध में, निर्देश आमंत्रित किया गया है, निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटराव (ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 201); बृंदाबन नाइक बनाम निर्वाचन आयोग (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1609); आदि में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की शृंखला है। इसी प्रकार के कई अन्य मामलों में भी आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा उनको किए गए निर्देश पर इसी प्रकार की राय दी है। इस संदर्भ में, वर्तमान अर्जीदार श्री सुब्रमणियन स्वामी द्वारा की गई अर्जी जो टी.टी.वी. दिनकरण की अधिकथित निरर्हता के बारे में 2001 का निर्देश सं. 1 में आयोग की राय तारीख 11-7-2001 से संबंधित है, को भी निर्दिष्ट किया जाए।

4. उपर्युक्त निर्दिष्ट सुस्थिर संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व-निर्वाचन निरर्हता के मामले में श्री राहुल गांधी की अधिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन किसी भी तरह नहीं उठाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को ऐसी अधिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है। अतः वर्तमान अर्जी संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पोषणीय नहीं है।

5. वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस राय के साथ तदनुसार वापस किया जाता है कि उपर्युक्त के प्रभाव से यह संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन पोषणीय नहीं है।

ह./-

(बी. बी. टंडन)

निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली

तारीख : 24 जून, 2004

ह./-

(टी. एस. कृष्णामूर्ति)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./-

(एन. गोपालास्वामी)

निर्वाचन आयुक्त

[फा. सं. एच-11026(1)/2004-वि.-II]

एन. एल. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2004

S. O. 835(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas Dr. Subramanian Swamy had submitted a petition dated 5-6-2004 for the disqualification of Shri Rahul Gandhi, a sitting member of Lok Sabha, for being a member of that House under clause (d) and (e) of Article 102(1) of the Constitution of India read with Section 9(1) of the Citizenship Act, 1955;

And whereas President had sought the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution on the question whether Shri Rahul Gandhi had become subject to disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Rahul Gandhi, being a case of pre-election disqualification, if at all, cannot be raised before, or decided by, the President under Article 103(1) of the Constitution and that the present petition is, therefore, non-maintainable before the President.

Now, therefore, I, A. P. J. Abdul Kalam, President of India, do hereby decide that the petition of Dr. Subramanian Swamy is non-maintainable, and is therefore, rejected.

16th July, 2004

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

CORAM:

Hon'ble Shri B. B. Tandon

Hon'ble Shri T. S. Krishna Murthy Hon'ble Shri N. Gopalaswami

Election Commissioner

Chief Election Commissioner

Election Commissioner

Reference Case No. 1 of 2004

[Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India]

In re : Alleged disqualification of Shri Rahul Gandhi, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1) (d) & (e) of the Constitution of India read with Section 9(1) of the Citizenship Act, 1955.

In the matter of : Shri Subramanian Swamy

Vs.

Shri Rahul Gandhi

OPINION

This is a reference dated 15-6-2004 from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Rahul Gandhi, a sitting member of Lok Sabha, under Article 102(1) (d) & (e) of the Constitution of India read with Section 9(1) of the Citizenship Act, 1955.

2. The above question arose on the petition dated 5-6-2004, submitted by Dr. Subramanian Swamy, to the President of India, seeking the decision of the President under Article 103(2) on his petition relating to alleged disqualification of Shri Rahul Gandhi, elected to the Lok Sabha from Amethi Parliamentary Constituency at the general election held recently, for being a member of Lok Sabha under clause (d) and (e) of Article 102(1) of the Constitution of India read with Section 9(1) of the Citizenship Act, 1955.

3. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution of India the jurisdiction of the President to decide the question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in disqualifications incurred after election as a member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution, also arises only in case of *post-election* disqualification. Any question of *pre-election* disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provision of Art. 329(b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in *Election Commission Vs. Saka Venkata Rao* (AIR 1953 SC 201); *Brundaban Naik Vs. Election Commission* (AIR 1965 SC 1892); *Election Commission Vs. N. G. Ganga* (AIR 1978 SC 1609); etc. In several other similar cases also, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States. In this context, the opinion dated 11-7-2001 of the Commission in Reference Case No. 1 of 2001 which related to a petition by the present petitioner Shri Subramanian Swamy about alleged disqualification of T. T. V. Dhinakaran may also be referred to.

4. In view of the well settled constitutional position, referred to above, the question of the alleged disqualification of Shri Rahul Gandhi, being a case of *pre-election* disqualification, if at all, cannot be raised under Article 103(1) of the

Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre-election disqualification. The present petition is, therefore, non-maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution.

5. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103(2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1) of the Constitution.

Sd./-

(B. B. Tandon)

Election Commissioner

Sd/-

(T. S. Krishna Murthy)

Chief Election Commissioner

Sd./

(N. Gopalaswami)

Election Commissioner

New Delhi.

Dated : 24th June, 2004.

[F.No. H-11026(1)/2004-Leg. II]

N. L. MEENA, Jt. Secy. & Legislative Counsel